राजस्थान पत्रिका

संस्थापक

कर्पूर चन्द्र कुलिश

सफाई के संस्कार से होता है बदलाव

स्वस्थ जीवन के लिए साफ-सफाई की जरूरत तो हमेशा रही है, पर कोविड-19 महामारी के दौर में शिद्दत से इसे महसूस किया जा रहा है। अपने पिछले कार्यकाल में मोदी सरकार ने शहरों की स्वच्छता को प्राथमिकता में रखा था। इसके लिए जो प्रयास किए गए, उनमें शहरों की स्वच्छता रैंकिंग के लिए हर साल किया जाने वाला सर्वे भी है। दरअसल, यह एक प्रतियोगिता है, जिसे जीतने के लिए शहरी प्रशासन को खास पैमाने पर विशेष प्रयास करने होते हैं। जिन शहरों ने इसे प्रतियोगिता की तरह लिया है, वहां वाकई कायापलट हो गई है। उदाहरण के लिए इंदौर को ही लें। दस लाख से ज्यादा आबादी वाली श्रेणी में पिछले चार सालों से इंदौर स्वच्छता रैंकिंग में अव्वल बना हुआ है। जाहिर है इसका श्रेय इंदौर नगर निगम को जाता है पर, उसके लिए भी यह इतना आसान नहीं रहा होगा और न ही सिर्फ निगम के प्रयास से ऐसा होना संभव है। श्रेय इंदौर के वाशिंदों को भी देना होगा, जिन्होंने अपनी आदतें बदलीं और न सिर्फ अपना घर बल्कि, आस-पास के इलाकों को भी स्वच्छ रखने को अपना कर्तव्य बनाया।

इंदौर, सूरत और कुछ अन्य शहरों के अच्छे प्रदर्शन को देखकर देश के बाकी शहरों को भी इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यही समय की जरूरत है। यदि शहरी प्रशासन साफ-सफाई को अपना मिशन बना ले, तो रैंकिंग सुधारना इतना मुश्किल भी नहीं है। इंदौर इस बात का भी उदाहरण है कि प्रशासन की ईमानदार पहल में शामिल होने के लिए जनता हमेशा तैयार रहती है। यदि इंदौर के लोग आज कारों में डस्टबिन लेकर चलते हैं कि रास्ते पर कचरा न फेंकना पड़े या सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल की उनकी आदत बदल गई है, तो यही कहना ज्यादा उचित होगा कि उन्होंने स्वयं में सफाई का संस्कार विकसित कर लिया है। यही वह बात है जो साफ शहरों को अन्य शहरों से अलग करती है, लेकिन इसके लिए प्रशासन को सबसे पहले आगे आना होगा। चमचमाती सड़कों को देखकर शायद ही कोई उसे गंदा करना चाहेगा। जब सड़कें या सार्वजनिक स्थान पहले से ही गंदे हों तो वहां कचरा फेंकने में किसी को हिचक नहीं होती है। कचरा घर से उठाने की व्यवस्था चाक-चौबंद हो तो गंदगी नालों को जाम नहीं करेगी और बारिश का पानी शहर को डुबोने की बजाय धोने का काम करेगा। नागरिक सजगता नदी-नालों पर अतिक्रमण नहीं होने देगी और योजनाबद्ध शहरी विकास कई ऐसी समस्याओं का समाधान कर देगा, जिसके लिए हम अभी काफी जद्दोजहद कर रहे हैं। हालांकि हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि रैंकिंग में स्थान लाने की प्रतियोगिता जीत लेना हमारा मकसद नहीं हो सकता। मकसद है सफाई।

आत्म निर्भर भारत का सपना हो सकता है साकार यदि...

कोरोनाकाल के संकट में छिपे अवसरों को पहचानें

राजस्थान, मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ परंपरागत रूप से मानव संसाधन संपन्न राज्य हैं, जहां से लोग काम के लिए दूसरे राज्य जाते हैं

संकट में भी अवसर छुपा होता हे। कोरोना महामारी भी विश्व के समक्ष कई चुनौतियों के साथ ही कुछ अवसर भी लाई है। अब यह व्यापक तौर पर स्वीकारा जाने लगा हे कि कोरोना संकट से उबरने के बाद भारत बड़ी आर्थिक ताकत बन कर उभरेगा। देश के भीतर भी राज्यों के बीच प्रतिस्पर्द्धा देखने को मिल रही है। हिन्दी भाषी राज्य सूझ-बूझ से बेहतर कर सकते हैं। राजस्थान,मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ परंपरागत रूप से मानव संसाधन और प्रतिभाओं से संपन्न राज्य हैं, जहां से लोग काम के लिए दूसरे राज्य जाते हैं। राजस्थान के गलीचा कारीगरों की मांग देश भर में है तो सफल सीए और वकील जोधपुर, बीकानेर और भीलवाड़ा के हैं।

संदीप घोष
लेखक, ब्लॉगर और बिजनेस लीडर, लीडरशिप कोच

कोटा शहर स्थानीय के साथ ही अन्य राज्यों के छात्रों का भी पढ़ाई के लिए स्वागत करता है। ये सब स्थानीय प्रतिभाएं विगत कुछ वर्षों से रोजगार के लिए अन्य राज्यों को पलायन कर गए थे। कोरोना संकट के बाद लोगों को इतना तो समझ आ गया है कि डिजिटल युग में दूरियां घट गई है। मुंबई से लेकर रायपुर,जबलपुर या उदयपुर से भी 'वर्क फ्रॉम होम' संभव हुआ। कोरोना संकट से निपटने के बाद बड़े शहरों पर जनसंख्या घनत्व कम करने का दबाव होगा ताकि किफायत के साथ बेहतर जीवन स्थितियां उपलब्ध करवाई जा सकें। कुछ लोग अपने गृहनगर लौट जाएंगे तो ऐसा करना आसान होगा।

अब नए उद्योग लगाने वालों को कम जनसंख्या वाली ऐसी जगहों की तलाश होगी, जहां सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्वच्छ वातावरण वाला कार्यस्थल उपलध करवाया जा सके। कोरोना काल के बाद कामगार शायद ही अपना गांव छोड़कर कहीं दूर काम करने जाएं। दूरस्थ शिक्षा और टेली मेडिसिन शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में नई क्रांति ला सकते हैं। इससे इंदौर और जयपुर के आइटी केंद्रों के लिए नई उमीद जगी है, जहां क्षमता होते हुए भी प्रगति नहीं हो पा रही थी। लोग अब पढ़ाई करने या इलाज करवाने के लिए शायद ही दूर के शिक्षण संस्थान या अस्पतालों में जाएं। अब छात्र हॉस्टल, बोर्डिंग स्कूल या उच्च शिक्षण संस्थान के लिए विदेश जाने को प्राथमिकता नहीं देंगे। इसी प्रकार कोरोना संकट के दौरान आस-पास मौजूद स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं का महत्व भी समझ आने लगा है।

राज्य सरकारों को इस अवसर को पहचानना होगा। गत कुछ वर्षों से मध्य-पश्चिमी भारत में बिजली-सड़क के आधारभूत ढांचे में उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिली। ई-कॉमर्स के युग में 'वोकल फॉर लोकल' और 'आत्म निर्भर भारत' का सपना साकार करना भी आसान है। ई-कॉमर्स से स्वदेशी उत्पादों को हर जगह पहुंचाया जा सकता है। लेकिन व्यतिगत उद्यमशीलता जरूरी है, ये सरकारें नहीं करेगी।

विदेशी कंपनियां आएंगी तो राज्यों के बीच प्रतिस्पर्द्धा का मुख्य आधार 'ईज ऑफ डुइंग बिजनेस' होगा। स्लोगन-विज्ञापनों से इतर असल काम करना होगा। सक्रिय अधिकारियों, पारदर्शिता और भूमि व श्रमिक नियमों में व्यावहारिक बदलाव जरूरी हैं। श्रमिकों को कौशल विकास और प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी सरकार की होगी।

इसे साकार करने के लिए राज्य सरकारों को इसे तुरंत एक 'मिशन' का रूप देना होगा। यानी ऐसा रवैया अपनाना होगा कि 'अभी योजना तैयार करो और अगले क्षण उस पर काम शुरू हो जाए। हालांकि फिलहाल कोरोना से जंग पर काम करना पहली प्राथमिकता है और कोरोना काल के बाद की कार्य योजना बनाने का समय है। भविष्य अनिश्चित है लेकिन एक बात तय है कि कोरोना संकट समाप्ति के बाद सब कुछ बदला सा होगा।

देश में स्वस्थ लोकतंत्र का तकाजा है कि...

राजनीतिक दल खुद ही करें आय-संपत्ति का खुलासा

पिछले 15 वर्षों से राजनीतिक दलों की भरसक कोशिश रही है कि मतदाताओं को चुनावी फंडिंग के बारे में पता न चले

लोकतंत्र में राजनीति और चुनावों में पैसे की भूमिका बढ़ती जा रही है। कई रिपोर्टों में सामने आया कि 2019 के चुनावों में अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव से ज्यादा पैसा खर्च हुआ। इससे लोकतंत्र, चुनाव और नागरिकों पर क्या प्रभाव पड़ता है; यह जानने के लिए चुनावों के तीन महत्वपूर्ण घटक मतदाता, राजनीतिक दल और चुनावों में चंदा देने वालों के उद्देश्यों को समझना होगा। मतदाता सुशासन चाहते हैं। वे चाहते हैं कि कर के रूप में वे सरकार को जो पैसा देते हैं, उसका उपयोग सरकार नीति निर्माण और उन सेवाओं की बेहतरी के लिए करे।

त्रिलोचन शास्त्री
आइआइएम बेंगलूरु में प्रोफेसर, एडीआर के संस्थापक अध्यक्ष

राजनीतिक दलों का सत्ता में आना ही लक्ष्य होता है। जो लोग चंदा देते हैं,वे चाहते हैं कि जीतने के बाद उन्हें फायदा मिले। चंदा देने वाले लोग या तो किसी प्रकार की कानूनी जांच से बचे रहने के इरादे से चंदा देते हैं या वे कहते हैं कि पार्टियों ने उनसे जोर जबरदस्ती से चंदा लिया है। कुछ ही ऐसे हैं, जो जन कल्याण के कार्यों के लिए पार्टी को चंदा देते हैं। कुछ प्रतिष्ठित एजेंसियों ने सार्वजनिक स्तर पर जो आंकड़े उपलब्ध करवाए हैं, उनसे ज्ञात होता है कि 2019 के लोकसभा चुनावों में 50 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा हुआ था। सवाल है कि ये पैसा आता कहां से है? राष्ट्रीय दलों द्वारा आधिकारिक तौर पर घोषित आय का आकलन करें तो पाएंगे कि 2004 से लेकर 2019 के बीच सभी राजनीतिक दलों की कुल आय 11 हजार करोड़ रूपए ही थी, फिर बाकी खर्च कैसे मैनेज हुआ? राजनीतिक पार्टियां सिर्फ और सिर्फ अगले चुनाव के लिए चंदा जुटाने में लगी रहती हैं।

मौजूदा स्थिति को तीन चरणों में समझा जा सकता है। पहला, राजनीतिक दलों द्वारा बताए गए चंदा उगाही के आंकड़ों में वृद्धि देखी गई। 2013-14 के आम चुनाव से पहले यह राशि 1,500 करोड़ से थोड़ी ज्यादा थी। 2018-19 तक ये 6,400 करोड़ हो गई। कुछ पैसा अघोषित भी हो सकता है। दूसरा, लोकसभा में आपराधिक पृष्ठभूमि के सांसदों की संख्या 2009 की 21 से 2019 में 43 फीसदी हो गई। तीसरा, आपराधिक रेकॉर्ड वाले धनी उम्मीदवारों के चुनाव जीतने की संभावना मध्यमवर्गीय ईमानदार उम्मीदवारों के मुकाबले ज्यादा होती है।

अन्य देशों में राजनीतिक दलों की फंडिंग को लेकर अधिक पारदर्शिता होती है। देश के कुछ कॉर्पोरेट हाउस अक्सर जांच के घेरे में रहते हैं और वे राजनीतिक पार्टियों के भी करीबी हैं। ऐसे आरोप भी लगते हैं कि पार्टियां इन व्यावसायिक घरानों को फायदा पहुंचाती हैं। चूंकि पुलिस और सीबीआइ राजनीतिक दलों के प्रभाव में होते हैं। इसलिए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होने की संभावना भी नगण्य रह जाती है। इस संपूर्ण 'व्यवस्था' में लोक कल्याण की नीतियां और बजट आवंटन भी प्रभावित होता है। सामाजिक क्षेत्र के व्यय में कटौती हो जाती है। इस बीच, ब्याज दरों में कटौती और आयकर में छूट संबंधी उपायों का फायदा भी कॉर्पोरेट घरानों को मिलता है। मान लीजिए, एक सेवानिवृत्त व्यक्ति ने यदि बचत के लिए फिक्स डिपोजिट करवा रखा है तो ब्याज दर कम होने से उसको अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। दूसरी ओर कर्ज में डूबे व्यावसायिक घरानों को ब्याज दर कम होते ही लाखों का फायदा हो सकता है।

पिछले 15 वर्षों से राजनीतिक दलों की भरसक कोशिश रही है कि मतदाताओं को चुनावी फंडिंग के बारे में पता न चले। चुनावी बॉन्ड इसी कोशिश का व्यापक रूप है। स्वस्थ लोकतंत्र का तकाजा है कि राजनीतिक दल स्वत:प्रेरणा से अपनी आय और संपत्ति का सही ब्यौरा सार्वजनिक करें और विश्व के समक्ष मिसाल कायम करें।

नवाचार

वर्कआउट से पावर!

कसरत के दौरान बहने वाला पसीना सुपर कैपेसिटर के जरिए चार्ज करेगा गैजेट्स

जी हां, सुबह-शाम की कसरत से पसीना बहाकर आप जो पावर बनाते हैं उससे बैट्री चार्ज हो सकती है। ग्रीन एनर्जी की दिशा में वैज्ञानिकों ने बड़ी सफलता हासिल की है। वैज्ञानिक ऐसे एनर्जी स्टोरेज सिस्टम विकसित कर रहे हैं जिससे कि पसीने में मौजूद लवण (सॉल्ट) से सुपर कैपेसिटर को चार्ज किया जा सकेगा। फिर इस संचित ऊर्जा से एईडी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चलाया जा सकेगा। सुपर कैपेसिटर बैट्री के समान ऊर्जा को संचित रख सकते हैं। पसीन से चार्ज होने वाले इन कैपेसिटर्स को पहला भी जा सकेगा। स्कॉटलैंड सिति यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक रविन्दर दहिया के अनुसार परंपरागत बैट्री में कई प्रकार के हानिकारक रसायन होते हैं। लेकिन इन सुपर कैपेसिटर में ऐसा नहीं होता है।

यूनिवर्सिटी ऑफ कैलीफोर्निया बर्कले की वैज्ञानिक मल्लिका बारिया के अनुसार पसीने को अक्सर बेकार माना जाता है लेकिन इससे कैपेसिटर्स को चार्ज किए जाने की अद्भुत क्षमता होती है। कपड़ों पर लगे कैपेसिटर पसीने को सोखते हैं। पसीने में लवण होता है। लवण के हर अणु में आयोन का पेयर होता है। एटम इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं और आयोन पॉजिटिवली चार्ज। न्यूयॉर्क की बिंगहैम्पटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक सीयो चोई के अनुसार पसीना त्वचा से निकलने वाला ऊर्जा स्रोत है। इसका इस्तेमाल करके कम पावर वाले गैजेट्स को चार्ज किया जा सकता है। पसीने का उपयोग आने वाले समय में फ्यूल सेल को बनाने में भी किया जा सकता है। फ्यूल सेल के माइक्रोब्स के जिरए भी ऊर्जा का उत्पादन भविष्य में संभव है।

आत्म-दर्शन

संतों का साथ न छोड़ें

व्यक्ति में चाहे कितने भी दुर्गुण हों, उसे कभी भी संतों का संग नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि संत ही हैं, जिनके साथ होने से दुर्गुणी व्यक्ति को भी प्रभु के दर्शन हो जाते हैं। सुग्रीव की छवि भगोड़ा, कायर, आलसी और भोगी की थी, लेकिन उसके अंदर एक सबसे अच्छा गुण यह था कि उसकी मित्रता हनुमान जैसे संत से थी। इसके कारण सुग्रीव को प्रभु राम के दर्शन हो गए। संतों के संग के कारण मनुष्य के दुर्गुण छूट जाते हैं। संत ही हैं जो प्रभु का दर्शन करा सकते हैं। संतों का साथ व्यक्ति को बड़ी-बड़ी मुश्किलों से बचा लेता है।

विजय कौशल जी महाराज
श्रीरामकथा के आधार पर प्रवचन के लिए प्रसिद्ध

यदि अनजाने में या जानबूझकर भी कोई भूल हो जाए तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। वह भूल कहलाती है, लेकिन यदि उस भूल को दोबारा किया जाए तो वह अपराध हो जाती है और उसका दंड भोगना पड़ता है। जो व्यक्ति भगवान को अपना सर्वस्व समर्पण कर देता है। भगवान उसका योगक्षेम स्वयं वहन करते हैं। उसकी सुरक्षा और सम्मान का दायित्व स्वयं लेते हैं। भगवान खोजे नहीं जाते, बल्कि पुकारने पर भगवान तत्काल भक्त को उन्हें दर्शन देकर उनके दुख दूर करते हैं। इसलिए हमेशा सत्संग करना चाहिए और प्रभु का स्मरण लगातार करते रहना चाहिए।

आर्ट एंड कल्चर

भावनात्मक विरोध का डिस्लाइक आंदोलन

सड़क 2 के ट्रेलर के रेकॉर्ड डिस्लाइक के तार सुशांत की मौत से भी जुड़े हैं

आंकड़े बताते हैं कि 1980 की सुपहिट फिल्म 'सड़क' के सिक्वल 'सड़क 2' के ट्रेलर को यू ट्यूब पर रिलीज के तीन दिनों के अंदर 6.5 लाख लाइक्स के बरक्स 1.1 करोड़ डिस्लाइक मिले। डिस्लाइक करने वाले इतने उतावले थे कि मात्र 7 घंटे के अंदर रेकॉर्ड 15 लाख डिस्लाइक इसे मिले। 3 मिनट के इस ट्रेलर का व्यू टाइम औसतन 22 सेकंड था,मतलब लोगों ने इसे सिर्फ डिस्लाइक करने के लिए क्लिक किया। हिंदी सिनेमा के इतिहास में किसी ट्रेलर के डिस्लाइक को आंदोलन की शक्ल देने की यह पहली घटना है। यह आंदोलन क्यों,तो इसका उत्तर बहुत भावनात्मक सा मिलता कि यह नेपोटिज्म का विरोध है। महेश भट्ट का विरोध है। अलिया भट्ट का विरोध है,क्योंकि इस सबके तार कहीं न कहीं सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ते हैं।

विनोद अनुपम
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त कला समीक्षक

नेपोटिज्म के तार करण जौहर से भी जुड़ते हैं,और जाह्नवी कपूर से भी। सो इनकी फिल्म 'गुंजन सक्सेना' के बायकाट का अभियान चला। हिंदी दर्शकों की उदारता को याद करें तो ट्रेंड चौंकाता है। ये वही दर्शक हैं जिन्होंने आमिर खान की 'पीके' को सर्वकालिक हिट फिल्मों में जगह दिलाई थी, ये वही दर्शक हैं जिन्होंने 'पद्मावत', 'फिजा','मुल्क' जैसी फिल्मों को तमाम विवादों के स्वीकार किया।

लेकिन फिल्म जब बन जाती है तो वह किसी एक आर्टपीस में बदल जाती है, जिसके मूल्यांकन के लिए तय मानक हैं, विश्लेषण की अपनी कसौटी है। व्यक्तिगत द्वेष पर किसी मूल्यांकन उस कृति के साथ सौंदर्यबोध से भी अन्याय है। किसी भी क्षेत्र में नेपोटिज्म का विरोध होना चाहिए, लेकिन यह सोचना तो पड़ेगा, क्या राजकपूर, ऋषि कपूर, रणबीर कपूर नेपोटिज्म के उदाहरण हैं, क्या आलिया और ऋतिक रोशन ने अपने को प्लव नहीं किया है? सुशांत की मौत के षडयंत्र में जो भी शामिल हैं, उनका विरोध हो। लेकिन उसके लिए संवैधानिक व्यवस्था है। लेकिन बिना किसी वैचारिक आपत्ति के निजी कारणों से सिनेमा या ट्रेलर के विरोध की कतई सराहना नहीं की जा सकती। फिल्म जब बन कर तैयार होती है तो वह किसी एक करण जौहर या महेश भट्ट का नहीं रहती। सैकड़ों-हजारों लोगों की भी उसके निर्माण में भूमिका होती है, जिसे हम अनजाने में आहत करते हैं।

हांगकांग: वर्चुअल फूड फेस्टिवल लेकिन स्वाद वही पुराना

कोरोना काल के कारण इस बार अक्टूबर में होने वाला हांगकांग फूड फेस्टिवल वर्चुअल (आभासी) होगा। दुनिया के टॉप-10 फूड फेस्टिवल में शामिल इस आयोजन में शेफ अपनी पाक कला का प्रदर्शन करेंगे। ग्राहक ऑनलाइन ऑर्डर कर डिशेज और व्यापारिक ऑर्डर दे सकेंगे।

तकनीक से महामारी का मुकाबला

साइंस &टैक

ब्लूमबर्ग
एमी थॉमसन, सूजी रिंग

कोरोना वायरस जैसी महामारी के बाद वैज्ञानिकों ने इसका इलाज खोजने के लिए दिन-रात एक कर दिए, हालांकि नतीजे पर अभी नहीं पहुंचे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस इस दिशा में शोधकर्ताओं के लिए कारगर हथियार साबित हो सकता है। हालांकि मौजूदा महामारी के लिए इस तकनीक के लिए शायद काफी देर हो चुकी है, लेकिन भविष्य में किसी अन्य प्रकोप के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ढेरों आंकड़ों को खंगालकर यह तकनीक बता सकती है कि इसके लिए क्या उपचार हो सकते हैं और कैसे इसे आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। दवा के लिए काम करने वाले स्टार्टअप एक्सेंसिया लिमिटेड के लिए काम कर रहे ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड विवि के सीईओ एंड्रयू हॉपकिन्स दवा की खोज के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता को प्रशिक्षित करने वालों में हैं। उनका आकलन है कि अगले दशक में 18 से 24 माह के भीतर उपचार की प्रक्रिया शोध से क्लीनिकल ट्रायल तक पहुंच सकती है। एक्सेंसिया लिमिटेड ने ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के इलाज के लिए नया यौगिक तैयार किया है, जो प्रारंभिक अनुसंधान के एक वर्ष के भीतर प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए तैयार है। दावा है कि यह नियत प्रक्रिया से पांच गुना तेजर से विकसित किया गया है।

कैंब्रिज स्थित हीलेक्स का दृष्टिकोण भी लगभग वैसा ही है। लेकिन यह मशीन लर्निंग के जरिए मौजूदा दवाओं के नए विकल्प तैयार कर रही है। दोनों कंपनियां प्रभावी उपचार खोजने के लिए एल्गोरिद्म की सूचनाओं का प्रयोग कर रही हैं। दोनों ही इस पूरी प्रक्रिया में एआई के साथ काम करने के लिए शोधकर्ताओं का सहयोग ले रही हैं।

एक्सेंसिया में ड्रग डिजाइनर यौगिकों की खोज के लिए एल्गोरिद्म को रणनीति बनाने में मदद करते हैं। जबकि हीलक्स एआई की भविष्यवाणी शोधकर्ताओं को भेजती है, जो डेटा का विश्लेषण कर उपचार की योजना बनाते हैं। हीलक्स के वैज्ञानिक नील थॉम्पसन का कहना है कि इस तकनीक को कोरोनावायस जैसे प्रकोप के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। थॉम्पसन का कहना है कि हम रोग की प्रकृति के आधार पर दवा निर्धारित करते हैं। मेसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं पहले ही एआइ एल्गोरिद्म के इस्तेमाल से दवाओं पर मंथन कर रहे हैं। जिन दवाओं के ट्रायल पर वर्षों लग सकते हैं, एआइ के से उनका हल शीघ्र मिल सकता है। ये जीवन बचाने की पद्धति साबित हो सकती है, बशर्ते कि इस पर चरणबद्ध काम किया जाए। एआई जैव सूचना विज्ञान दृष्टिकोणों का उपयोग संभावित रोग लक्ष्यों की पहचान करने, चयन और प्राथमिकता देने के लिए कर सकता है,जो मानव शोधकर्ताओं को लगने वाले समय को कम कर सकता है। एक एआइ, असमान रूप से बड़ी मात्रा में कागजात संधारित कर सकता है, उन्हें व्यवस्थित कर सकता है, सरलीकृत रेखांकन और चित्र तैयार कर सकता है और प्रासंगिक खोज किए जाने पर तत्काल अपडेट प्रदान कर सकता है।

आपकी बात

जिम्मेदारी की अनदेखी

इंसान ने सीमेंट-कंक्रीट के जंगल तो बना लिए, किंतु प्रकृति को सहेजने का कार्य नहीं किया। बरसात के पानी को ना तो धरती में जाने के लिए जगह दी और ना ही बहकर नदी एवं जलाशयों में मिलने का स्थान। जिन जिम्मेदारों के ऊपर इसका भार है, उन्होंने इसकी अनदेखी की। नालों पर आशियाने भी बना लिए गए।

-अनिल अग्रवाल, भोपाल

नागरिक भी कम दोषी नहीं

जगह-जगह अतिक्रमण और पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से शहरों में बारिश के दौरान गली-मोहल्लों, बाजारों की नालियां सड़कें जाम रहती हैं। नालियों की सफाई नहीं होती। लोग भी लापरवाह हैं, जो कूड़ा करकट फैलाते हैं। इससे नाले-नालियों में जाम लगता है, जिससे पानी सड़कों पर आ जाता है।

-दीप्ति मिश्रा, कोटा

आज का सवाल: 'देशभर में सरकारी नौकरी के लिए एक परीक्षा कितनी उचित है?'

आपकी बात पर अपनी राय भेजने के लिए **98292-66081** वॉट्सऐप करें

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की प्रतिक्रियाएं

पत्रिकायन का सवाल था, 'शहरों के लिए आफत क्यों बन जाती है बारिश?' इस समस्या पर कई पाठकों ने मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दी हैं। इनमें से कुछ प्रतिक्रियाओं को ऑनलाइन दिया रहा है।

इसे स्कैन करें

t.ly/f9l6